implement that policy and take every possible step to improve the efficiency and competitiveness of the public sector, the situation may improve. When there is such commitment in the words of the hon. Minister, I think, I can take his assurance as a basis for not pressing this resolution.

Sir, the last point is, the hon. Finance Minister said in his Budget speech that the hon. Minister for Industry would make a statement and that statement, I think, would be on the public sector. There is some political problem in the recent period. So, I cannot press him to make that statement in this session itself. But, at least, during the next monsoon session of Parliament, the Government must come forward with a White Paper or a black paper or a statement, as promised by the hon. Finance Minister so that there would be a good opportunity for the House to discuss, at length, and also take up concretely what project or which industries or which companies can be revived, how they can be revived and some positive suggestions may also come up. I request the hon. Minister, at least, to think about making a statement in whatever form he thinks fit. That is left to him. That is for him to decide. But there should be a proper opportunity to discuss on the initiated policy on the public sector in the coming session of Parliament, if it is not possible now. Thank you, Sir.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): Sir, the hon. Member has referred to a White Paper. We did not promise any White Paper. What we are doing is, we are preparing a paper for giving maximum autonomy to the *Navaratnas*. That is one aspect. Another aspect is, we went to give managerial and financial autonomy to other profit making enterprises. I think, we need not wait till the next session; within a fornight or so, the Government will come out with a press-note ... *(Interruptions)*... I think the hon. Member for his cooperation ...*(Interruptions)*... It is a question of automony i.e., total autonomy to the Navaratnas and managerial and financial autonomy to other public sector undertakings.

SHRI N. GIRI PRASAD: No, Sir. Let there be no confusion on this issue. The hon. Finance Minister stated in his Budget speech that the hon. Minister for industry would make a statement, maybe, on the same lines, but that should be done in the House. Even if the Government announces during the inter-session period, there should be some opportunity for the Parliament to discuss it ...*(Interruptions)*...

SHRI MURASOLI MARAN: Let us not wait till the next session which is going to take place sometime in the month of July ...*(Interruptions)*... What I am saying is, we prepare it and I think, the Cabinet will approve it and we will release it to the Press very soon and anytime, any day, the House may discuss, if it wants.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): But, I think what he mentions is that there should be a scope to discuss that paper in the House. Anyway, since he is not pressing for the Resolution, I ask for the sense of the House. Has he the leave of the House to withdraw the Resolution?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): We move on the next Private Member's Resolution. Shri Jalaludin Ansari.

Acute Scarcity of Drinking water in villages

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं कि:

> यह सभा इस तथ्य पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50वें वर्ष में भी देश के हजारों गांवों में पेयजल की अत्यंत कमी है, अपनी गहरी चिंता व्यक्त

करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह इस मूल समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम तैयार करने हेतु तत्काल कदम उठाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): आप बोलिए।

श्री जलालुदीन अंसारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं देश की जनता की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर इस सदन के माध्यम से और आप के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। महोदय, आज 40 साल के योजनाबद्ध विकास के बावजूद देश की ग्रामीण जनता और शहरी जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है। देश की ग्रामीण आबादी की करीब 45 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल पूर्ण मात्रा में प्राप्त नहीं है और दूसरे गांवों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, यह हमें वर्ष 1994 के एक आंकड़े से पता चलता है।

महोदय, खुशी की बात है कि हम देश की आजादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाने पर विचार कर रही है इस 50 साल की आजादी में जीवन के किन-किन क्षेत्रों में हम ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इस 50वीं सालगिरह के अवसर पर हम अपनी उपलब्धियों को भी गिनाने जा रहे हैं और आगे क्या किया जाये, इस पर भी सरकार देश की जनता के सामने कुछ विशेष योजना लाने का विचार कर रही है।

आप सभी जानते हैं कि जीवन की कुछ जरुरी आवश्यकताएं हैं, जैसे मकान, कपड़ा, दवा लेकिन सब से बड़ी आवश्यकता है पेयजल और इस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन यह देश जोकि गांवों का देश है और जहां सब से बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है, इन 50 सालों में उसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी कोसों दूर से लोग पानी ढोकर लाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। फिर शुद्ध जल न मिलने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उन में खासकर डायरिया, टाइफाइड और हेपटाइजिटस हैं। इस के अलावा शुद्ध जल न मिलने से मनुष्य के पेट में कीड़े पैदा होते हैं और उस कारण भी तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। महोदय अपने देश में आज स्थिति यह है कि पढ़े-लिखे लोगों का भी एक बड़ा हिस्सा उबला हुआ पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता है।

इस संबंध में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मार्केट रिसर्च एजेन्सी ने एक सर्वे किया मेजर सिटीज का, बड़े शहरों का और उन लोगों का, जो हाइएस्ट इन्कम ग्रुप के लोग हैं। ऐसे 3000 घरों का उसने सर्वे किया तो पता चला कि 75% वे लोग भी उबला हुआ पानी नहीं पीते हैं। उनके वहां वाटर टैप हैं, लेकिन वह बॉयल वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस ग्रुप में करीब 55 प्रतिशत लोगों के पास पानी के टैप है, जो फिल्टर पानी का इस्तेमाल करते हैं।

महोदय, सरकार ने गांव में पानी देने के लिए जो नार्मस तय किया है, उसके अनुसार 40 लीटर शुद्ध जल प्रति व्यक्ति प्रति दिन देने की योजना है। सरकारी नार्म्स के अनुसार 250 व्यक्तियों के आधार पर एक हैडपंप, जिसको चापाकल या स्टेंड पोस्ट कहते हैं, देने का है। इसके अलावा और भी नार्मस है, लेकिन इन्हीं दो नार्मस को अगर हम देखें तो क्या गांव में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर शुद्ध जल मिलता है? इसमें कोई जांच की बात नहीं है। यह स्पष्ट सच्चाई सबके सामने है। गांव के अंदर जो स्थिति है और पेयजल की जो व्यवस्था है। इसी तरह से 250 व्यक्ति पर एक चापाकल भी आज नहीं है और न ही स्टेंडपोस्ट है, जिसके जरिए कि उनको शुद्ध जल दिया जा सके।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा जैसा आप सभी जानते हैं, अब गरमी का मौसम आ गया है और गदला जल भी हर गांव में हर जगह मिलना कठिन है। इस तरह की सरकार की योजनाएं चली हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना अब समाप्त होने जा रही है और नवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है और उसका एप्रोच पेपर हम लोगों के सामने आया है। मुझे यह कहना है कि 40 साल में योजनाबद्ध विकास के जो तरीके अपनाए गए, उसमें जो जनता की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, उस समस्या का समाधान नहीं हो सका इन पिछले चार दशक में। सरकार का तो बड़े पैमाने पर यह दावा है कि चापाकल गांव में गाड़े गए हैं। गाड़े भी गए हैं, यह सच्चाई भी है।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टेट में आप इसकी जांच करा लें, किसी एजेंसी से जांच करा लें तो आप पाएंगे कि पिछले कई वर्षों में जो चापाकल गाड़े गए, उसका एक बड़ा हिस्सा बेकार है, उससे पानी नहीं निकालता है। नॉनफंशनिंग है और इसका प्रधान कारण यह है कि चापाकल की देख-रेख की जवाबदेही न ग्रामीणों पर है और न ही पी०एच०ई०डी० के कर्मचारी उसकी देख-रेख करते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इसको गाढ़ देता है, लेकिन इस विभाग के लोग कभी गांव में जाकर के उस चापाकल को देखते नहीं हैं, उनका मेकैनिक कभी जाता ही नहीं है और अगर वह

चापाकल बिगड़ गया है तो गांव के लोग उनको बनवाते नहीं हैं क्योंकि गांव के लोगों को यह जवाबदेही दी नहीं गई है। इस तरह से उसको न सरकार ठीक करती है और न ही गांव के लोग करते हैं, परिणाम यह होता है कि एक बड़ा हिस्सा, चापाकल, जो पेयजल उपलब्ध कराता था, वह बेकार पड़ा है, वह बर्बाद हो गया है, उसकी कोई देख-रेख नहीं होती है—न तो पी०एच०ई०डी० की तरफ से और न ही गांव के लोगों की तरफ से। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि गांवों में कूएं खुदवाए गए 10 फीट के, 20 फीट के या अढ़ाई मीटर की गहराई के और उसका उद्देश्य यह था कि इससे गांव के लोगों को पेयजल भी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ इसके पानी को सिंचाई के काम में भी लाया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है? मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं और वे जानते भी होंगे कि कई लेअर पर पानी मिलता है और फर्स्ट लेअर में जब पानी मिल जाता है तो वहीं चापाकल को गाड़ दिया जाता है क्योंकि कंट्रेक्ट सिस्टम है। सरकार कहती है कि हमारे विभाग के ज़रिए वह काम होता है लेकिन वह किसी न किसी एजेंसी से होता है, वह विभाग की ही होता है, उसमें ठेकेदारी प्रथा रहती है। तो वह उसको वहीं गाड़ देते हैं जहां उनको ऊपरी सतह पर पानी मिल जाता है और जब मार्च-अप्रैल का महीना आता है और उसकी सतह नीचे चली जाती है तो वह कूआं या चापाकल बेकार हो जाता है, बंद हो जाता है और उसका उपयोग किसी भी काम में नहीं हो पाता। यह वास्तविक स्थिति है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बिल्कुल सच्चाई है, इसकी आप किसी भी स्तर पर, किसी भी राज्य में, जिले में जांच करा लें तो देश के अधिकांश भागों में आपको यही स्थिति चापाकल और कूओं के बारे में, जिनको सरकार ने खुदवाया, मिलेगी। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि चापाकल जो गाड़े गए हैं, या गाड़े जाएंगे, उनकी मैंटेनैंस या रख-रखाव की जिम्मेदारी पी०एच०डी० डिपार्टमेंट की हो और अब जब कि पंचायती राज कायम हो गया है तो पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों और गांवों की भी यह जवाबदेही होनी चाहिए कि वह उसका रख-रखाव करें तभी जो काम आप करते हैं, उसका लाभ गांव के लोगों को पेयजल के लिए मिल सकता है। तो यह जो त्रुटियां है, कमजोरियां है, उनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

महोदया, करीब-करीब पूरे देश के अंदर जल स्तर, वाटर लेवल, बड़ी तेज़ी से पिछले कुछ वर्षों से भागता चला जा रहा है, नीचे गिरता चला जा रहा है। इस सदन में भी इस बारे में कई बार जब सवाल उठाए गए तो पूर्व प्रधान मंत्री ने भी इस बात को कहा और मंत्री महोदय ने भी कहा कि पानी का लेवल भाग रहा है, जो एक नई समस्या है, एक नई प्राब्लम है।

इस प्राॅब्लम को हल किए बिना पेयजल को आप उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हमने पहले कहा कि हम लोग गांव के रहने वाले है। हमें याद है कि पुराने समय में जब लोग कुआं खोदते थे तो जून के महीने में खोदते थे क्योंकि जून के महीने में पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता था। इस तरह से बहुत गहराई तक कुएं की खुदाई होती थी और पानी निकलता था। इस तरह से गहराई तक खुदाई करने से पानी का स्तर किसी भी महीने में नीचे नहीं जाता था। आजकल कुएं कब खोदे जाते हैं? कभी अक्टूबर में खोद दिया, कभी नवंबर में खोद दिया, कभी जनवरी में खोद दिया। इन दिनों पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जब कि कुएं की खुदाई काफी गहराई तक होनी चाहिए ताकि जून और जुलाई के महीनों में पानी की प्राॅब्लम न हो। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, इस पर डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है, सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।

महोदय, आपकी योजनाएं, आपकी स्कीम्स तो लागू होती हैं लेकिन उसका जो फल आम जनता को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है, इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आज जो स्थिति है उसमें समुचित जल प्रबंधन की जरूरत है। जहां पानी की एक-एक बूंद के सही उपयोग के जरूरत है, वहीं अधिक से अधिक संचय की भी जरूरत है। यह कैसे होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 198 विकास खंडों में से तीन-चौथाई में भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इस रिपोर्ट में खासकर थार इलाके के बारे में जिक्र है कि वहां लगातार भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है। कुछ जिलों जैसे झुंझनू, सीकर, नागौर और पाली में तो प्रति वर्ष 20 से 40 सेंटीमीटर जल स्तर का घटता जाना एक चौंकाने वाली बात है। इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी जल स्तर घटते जाने का यह सिलसिला जारी है।

महोदय, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने ऐसे कुछ क्षेत्रों का अध्ययन किया है और यह रिपोर्ट दी है कि जो आधुनिक पेयजल की योजनाएं हैं उनको तो लागू करना ही चाहिए लेकिन हमारे देश में पुराने समय में जिस तरह से जल संचय किया जाता था, उन तरीकों का भी अगर इस्तेमाल किया जाए, जल संचय के लिए दोनों तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा होगा। आधुनिक तरीकों में और सुधार किया जाना चाहिए।

इसमें जो गड़बड़ियां हैं, त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं इनको दूर किया जाए और इसको बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ जो कुछ पुराना जल संचय करने का तरीका था उसको भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए और मेरा सुझाव होगा कि इस पर भी सरकार विचार करे।...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): अंसारी जी, एक बात है पांच बजे खत्म होगा। अगर आप जवाब मांगते हैं मंत्री जी से तो मेरे ख्याल में थोड़ा और संक्षेप में रखते तो बेहतर होगा।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं।

†[شری جلال الدین انصاری: میں "سنکشیپ" میں ہی کہہ رہا ہوں۔]

SHRI YERRAN NAIDU: Sir, I have not received any information regarding this subject. That is why I request I may be allowed to reply on a later date.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): But, who is the Minister concerned to reply to this debate?

SHRI YERRAN NAIDU: This subject is not under my charge. So, I cannot reply to it just now.

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): यह तो पहले साफ हो जाना चाहिए कि कौन मंत्री इसका जवाब देगा। मेंबर साहब ने बाकायदा अपना नोटिस दिया है और बैलट पर नाम आया है। ...(व्यवधान)

श्री जलालुद्दीन अंसारी: आज हाऊस में उपस्थिति भी कम है, आज इसको समाप्त नहीं करके दूसरे दिन लिया जाए। हमारे कुलिग्स है नाम दिए हैं। जो हैं बोल लें। दो घंटे में तो पूरा भी नहीं होगा। साढ़े तीन बजे के बाद तो शुरू हुआ है, आज 5 बजे हाउस एडजोर्न होगा। बिजनेज एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है। अगर रस्म अदायगी करना है तो किसी भी समय इसको समाप्त करलें। हम समझते हैं कि यह गंभीर विषय है। ...(व्यवधान) आप और हमारे बहुत सारे विद्वान साथी हैं जिनको हमसे अधिक जानकारी है वह अपनी बात को रखेंगे। ...(व्यवधान) मेरा यह सुझाव यह है कि इस पर आप विचार करे कि इसको नेक्सट डे कॉन्क्लूड कीजिए। सदस्यों ने जो नाम दिए हैं वह हैं नहीं और जो हैं वह बोलेंगे और मंत्री जी के बारे में भी स्पष्ट होगा कि कौन मंत्री जी जवाब देंगे। यह मंत्री देंगे या दूसरे देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): आप बोलते रहिए।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ और भी सुझाव स्वयं सेवी संगठन का आया है और उन्होंने कई सर्वे भी किया है कि तीन साल, चार साल और उनका सुझाव है कि अभी जो जल संकट है उससे बचने का एक तरीका यह भी है कि हमारे पुराने जो तरीके हैं उसका भी उपयोग किया जाए। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के विशेषज्ञों का एक शोध संगठन है जिसका नाम—परम्परागत भारतीय जल प्रबंधन है और इस स्वयं सेवी संगठन की यह राय है कि पुराने समय में भारत के जल प्रबंधन का कोई शानी नहीं था और भविष्य में जल संकट से बचने के लिए हमें अभी से अपने पुराने प्रबंधन पर लौट जाना चाहिए।

जो नई हमारी तकनीक है उसको छोड़ दिया जाये और पूरे तौर पर पीछे लौट जायें यह मेरी राय नहीं है लेकिन उनके भी कुछ सुझाव हैं। जो पुराने जल संचय के तरीके थे वे किसी हद तक आज की परिस्थिति में सही हैं और वे कारगर हो सकते हैं इसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। कुछ जगहों का उसमें उदाहरण है। उसी तरह से उनकी रिपोर्ट में राजस्थान के अलवर जिले का उदाहरण दिया गया है। जहां तरूण भारत नाम के संगठन ने 1200 जोहड़ों का निर्माण करके स्थानीय जनता को पीने का पानी उपलब्ध करवाया है। एक अध्ययन करके जल प्रबन्धन के रूप में जम्मू के कुहल्स, हिमाचल प्रदेश के कुलस, उत्तराखंड के गुलस, महाराष्ट्र के पाट्स, लद्दाख के जिनगस, नागालैंड के जाबो, तमिलनाडु के एरिस, राजस्थान के बावड़ी जोहड और झालरा, गुजरात के विरदासों का उदाहरण दिया गया है जिसके जरिए वहां के लोग बड़े बांधों के द्वारा कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से पानी का प्रबन्धन कर लेते हैं। इसमें बिहार का भी एक उदाहरण दिया गया है। बिहार में संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बड़े-बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं को निरर्थक बताया गया है लेकिन हम इन परियोजनाओं को निरर्थक नहीं मानते हैं। उसके मुताबिक 1941 में बिहार के इन क्षेत्रों की 12.5 प्रतिशत भूमि सिंचित थी जो 1981 में घटकर 4.5 प्रतिशत ही रह गई। रपट के

†[ ]Transliteration in Arabic Script

मुताबिक सिंचित क्षेत्र में यह कमी 104 सिंचाई योजनाओं पर 900 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी रपट में इस परम्परागत जल संरक्षण तरीके को बढ़ावा देने के लिए गांव वालों को मौद्रिक प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में कहना यह है कि जो हमारे पुराने परम्परागत तरीके थे उनको आजकल बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। जिसकी वजह से भी हम जल का संचय नहीं कर पा रहे हैं। जो संचय परम्परागत तरीकों से पहले करते थे उस का पेयजल के रूप में भी उपयोग होता था और सिंचाई के लिए भी उपयोग होता था। मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, विशेषकर जहां पर हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, हरिजन भाई रहते हैं, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहते हैं, उन इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये क्योंकि हम इस साल आजादी की पचासवीं जयन्ती मना रहे हैं। आजादी की पचासवीं साल गिरह के अवसर पर भारत सरकार देश की जनता की जो एक महत्वपूर्ण पेयजल समस्या है जो दिल्ली में भी है, इस दिल्ली में आप और हम भी रहते हैं, रोज अखबारों में देखिए क्या स्थिति है। हम लोग तो बीआईपी इलाकों में रहते हैं इसलिए पानी नियमित मिल जाता है लेकिन इसी दिल्ली में गांव के इलाकों में पानी की क्या हालत है। लोग गांवों में कई-कई मीलों से पानी ढोकर के लाते हैं आप जरा उनके इस कष्ट का अंदाजा तो लगाइये। वह एक दो घड़ा पानी ढोकर लायेंगे तो वह उस में से कैसे खाना बनायेंगे, पानी पियेंगे, स्नान करेंगे और कपड़े साफ करेंगे? गांव के लोगों की पीने के पानी की जो कठिन समस्या है उसको दूर करने के लिए हम इस पचासवीं जयन्ती के अवसर पर इस सरकार से मांग करते हैं कि वह इसके लिए एक क्रेश प्रोग्राम सारे पक्षों पर विचार करके बनाये और एक निश्चित अवधि में यह निर्णय ले कि इस देश के सभी गांवों और शहरों में पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान करे और देश की जनता को पेयजल मुहैया कराने की एक योजना सरकार अतिशीघ्र बनाये। सरकार इस देश की जनता को पेयजल के संकट से मुक्ति दिला दें यही हमारा इस संकल्प में सरकार से अनुरोध है। मुझे विश्वास है कि हमारे जो साथी हैं वह इस समस्या पर दिलचस्पी लेते हुए अपने सुझाव देंगे और सरकार उन सुझावों पर विचार करके एक ठोस कार्यक्रम बनायेगी जिससे इस समस्या का निराकरण हो सके।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : Shri John F. Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Thank you, Mr. Vice-Chairman. It is a great shame and tragedy for the nation that in the 50th year of Independence, this Parliament has to debate a matter which is of vital importance to the nation. I can understand our debating questions of *roti, kapda* and *makan.* They are subsequent matters. But air and water are basic things for any human being to survive. I compliment my hon. colleague, Mr. Ansari, for bringing this resolution in the House to draw the attention of this Government.

In 1985, when the then Prime Minister Rajiv Gandhi came to office, I remember, he started five missions. Apart from the Technology Mission and Telecom Mission, the Drinking Water Mission was one of them. I do not know what the Government is doing about it, whether that Mission is still functioning or it has been given up by the Government. We have plans and plans. In the 50s, we started a Five-Year Plan and we have just completed the Eighth Five-Year Plan and we have stepped into the Ninth Five-Year Plan. I think our Planning Commission and the planners of this country have totally failed in helping the needy, poor people who live down in villages and rural areas. Day in and day out, we are faced with natural calamities. We have either droughts or floods. And millions and millions of gallons of water—fresh water—every day flows down from the Himalayas runs through the rivers of the Ganges or the Brahmaputra and flows into the Bay of Bengal or the Indian Ocean.

I do not think that the problem is that we do not have the natural resource. But we do not have a proper management. I can understand the problem of the Government that we do not have the financial resources to distribute this natural element among the poor people. In this House, we witness that there are disputes, inter-state disputes, and

whenever Cauvery is mentioned in this House, we see that the House is divided between Karnataka and Tamil Nadu. Water resource is a national wealth. I think it will be appropriate for the Government to see that the water throughout the country is taken as a national asset and it is not given as a private property to a State, for, we are federal. We have a federal system of Government. I feel it will be better if the Central Government steps in and sees that this basic resource is equitably distributed throughout the country.

Sir, I have mentioned wasting of water from the Himalayas through the Brahmaputra and the Ganges. At the same time, we see that we can pump fuel from the Kandla Port in Gujarat to the Mathura Refineries in U.P. If we can manage to do that, I do not know why we should fail to distribute this potable water, fresh drinking water, to the villages, to the far-flung areas of our country, specially to the desert areas of Rajasthan. I was mentioning the failure of the Planning Commission. I happened to attend a workshop in the Rural Development Institute in Hyderabad at Rajendra Nagar. We were told there that in the Thar Desert of Rajasthan, a foreign satellite could identify land-locked water which has been lying there are hundreds of years.

4.00 P.M.

Now when we have this technology, the satellite remote-sensing technology, I think that it will not be difficult for the Government to solve this problem, provided there is a will with the Government to see that the drought-prone areas in the country are connected with this National Water Grid on a priority basis. There are so many schemes with the Government now. I don't think that these schemes are implemented; the drinking water scheme, the tubewell scheme. Now we, the Members of Parliament, also are given funds under the Members of Parliament Local Area Development Scheme, but this Scheme cannot be properly implemented because you know that the stipulations of the Government are so severe that you have to have a community land, that you have to have a land which is under the Government. This Scheme cannot be just implemented because you can't have a scheme somewhere in a place which is far away from the villages where people reside. So, I think it will be appropriate for the Government to see that these schemes are revised to see that every house in a village is provided with these facilities. If there were land in the backyard, these facilities can be given to the people on a private land. That will also reduce the pressure on the Government water supply system. So, when we say 'the water supply system', we totally depend on the municipality or the panchayat which has no funds. You know there is a paucity of funds and the Government has recently privatised various sectors, especially the power sector. I would like to know from the Government whether they will also bring in some scheme so that the private sector can also have a say in it and that the private sector can also play a role in it. I know that the Government can compensate, the Government can subsidise, and I think, that is the only way to solve the problem of shortage of drinking water in the country. Sir, our planners have again failed. What happens is we provide a lot of funds for the public health system. Water-borne diseases are very common—V.C. cholera, V.C. typhoid, V.C. dysentery, V.C. gastro-enteritis. Instead of providing more funds for the health system, it will be better if we spend money on controlling and preventing these diseases, and I think, if the Government diverts more funds towards creating the facility of drinking water, that will go a long way. Sir, this problem has become so grave that I remember an incident which I want to narrate here. I was an observer for elections in Nagaland and the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, went there for an election campaign, and we were talking to the villagers; when he asked

them as to what they would require—my apprehension was that they would ask for some factory or some industry or some school or some college—all those people said, "We don't have drinking water!" And right across the State, you have the river Brahmaputra where the water flows down from the Himalayas and it is just pumped into the Bay of Bengal. If this could be the major problem of the people in Tribal areas, I do not know how many more years we will take to see that this problem of our people is solved. Sir, I don't think I have much more to add here. I applaud the spirit in which Mr. Ansari has brought this Resolution and I would request the Government to come out with a proposal and ask the Planning Commission to frame a proposal. It should come out with a proposal so that this problem can be sorted out with the help of the private sector in this country. Thank you very much, Sir.

श्री बंगारू लक्ष्मण (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय अंसारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा शुरू की है। हम लोग आज़ादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे है। यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी देश के 45 प्रतिशत गांव पूरी तरह से पीने के पानी से मोहताज हैं। उसके लिए पार्शियल स्कीम कवर की बात की जा रही थी और यह पता नहीं कि हम लोग पीने का पानी कब तक, किस वर्ष तक या कौन सी अवधि के अंदर दे पाएंगे। कहीं तो यह कहा जा रहा है कि यह शताब्दी पूरी होते होते हम पीने का पानी मुहैया करा देंगे। कहीं यह कहा जा रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने तक यह पूरा किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? सरकार क्या करना चाहती है इस दिशा में आज विचार करना बहुत आवश्यक है। सरकार ने यह माना है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में गांवों के अंदर पानी नहीं मिलता है। हर प्लान में हम लोग इसका इवैल्युएशन करते हैं और प्राब्लम विलेजेज जो हैं उनकी संख्या किसी न किसी प्रकार से लगभग कान्स्टेंट चलती आ रही है। जैसे पहली अप्रेल को यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही थी उस समय यह माना गया था कि 1 लाख 62 हजार प्राब्लम विलेजेज हैं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जिन विलेजेज को कवर करने की बात चल रही थी उसमें से 39 हजार गांव बाकी बच गए थे। इस प्रकार से 2 लाख 1 हजार गांव सातवीं पंचवर्षीय योजना तक आ गए थे। यही हिसाब उससे पहले की छठी पंचवर्षीय योजना में था। उसमें भी यही हिसाब लगाया गया था। वहां पर भी 2 लाख 31 हजार गांवों के अंदर पीने का पानी नहीं था या ये प्राब्लमेटिक विलेजेज थे इस प्रकार माना गया था।

योजनाएं तो काफी बन रही हैं। अभी पहले इसका नाम था "नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन"। इसको 1986 में शुरू किया गया। उसके बाद फिर इसका नाम 1991 में बदला "राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन"। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम लोग आज बैठकर यह तय कर सकते हैं, सरकार यह कहने की स्थिति में है कि अगली शताब्दी में यह एक समस्या बनकर नहीं रहेगी। इस समस्या को हम लोग किसी न किसी प्रकार से समाप्त करेंगे। क्या सरकार यह दावे के साथ कह सकती है। मुझे लगता है कि सरकार की अपनी दिक्कतें हैं। यद्यपि पब्लिक पोस्चर यह ले रही है कि दो हजार ईस्वी के अंदर हम पूरी तरह से इस प्राब्लम को साल्व कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने इस सदन के अंदर यह माना है कि एज आन 1.4.96 पूरी तरह से पीने का पानी जिन गांवों में नहीं है उन गांवों की गिनती 75 हजार है। जहां थोड़ी मात्रा में पानी की उपलब्धि है उन गांवों की संख्या 3 लाख 31 हजार 646 गिनायी गयी है। ऐसी स्थिति में यह नहीं लगता कि हम लोग क्या नवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको पूरा कर पाएंगे।

यह कहा जा रहा है कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गयी है और राज्य सरकारें इसको पूरा करने के लिए तत्पर हैं और लगी हुई है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में इस समस्या को पूरी तरह से हल करने में सफल नहीं हो पा रही है। हर पंचवर्षीय योजना के अंत में जो आंकड़े दिए जा रहे है उससे यह बात बिल्कुल साफ है जैसा कि मैने शुरू में कहा कि प्राब्लमैटिक विलेजेज—जहां पीने का पानी नहीं मिलता है—इस प्रकार के विलेजेज की संख्या लगभग हर पंचवर्षीय योजना पूरी होने तक कान्स्टेंट रूप से चलती आ रही है।

इसमें कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब 2035 के बाद शायद पानी की उपलब्धि भी इस देश के अंदर बहुत कम होगी। यह बड़ा दुर्भाग्य है। आज बाकी सब चीज़ें तो मिलती हैं, उपसभाध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि आप किसी भी गांव में जाइये, इस उम्र में आप भी सफर करते होंगे बाकी लोग भी ट्रेवल करते हैं, गांव के अंदर जब जाते है तो अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको कोका

कोला मिलेगा या फिर इसी प्रकार का सांफ्ट ड्रिंक मिल सकता है लेकिन पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां आपको दिन में भी शराब मिलेगी लेकिन एक गिलास पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। इस प्रकार की स्थिति आज है। इसलिए इस प्रस्ताव का बहुत महत्व है। सरकार को इस पर पूरी तरह से ध्यान लगाना पड़ेगा और निश्चय करना पड़ेगा। मैं नौवीं पंचवर्षीय योजना का एप्रोच पेपर देख रहा था कि कहीं पर शायद सरकार ने इस बात पर जोर देकर कहा हुआ हो दुर्भाग्य से इसको जितनी इंपार्टेंस देनी चाहिए उतनी इंपार्टेंस इसमें नहीं मिली है। यह भी सब को पता है कि केवल स्वच्छ जल नहीं मिलता है कहीं पर पीने का पानी तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ इतनी बीमारियां और इतने प्रकार के उसके अंदर रोग है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे फ्लोरोसिस है। यह समस्या बड़ी गंभीर है। 14 राज्यों के अन्दर यह समस्या है 150 जिलों के अंदर ऐसे गांव है जहां पीने केन पानी में फ्लोरोसिस की ज्यादा मात्रा होने के कारण कई समस्यायें खड़ी हो रही हैं। उसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल के अंदर आर्सेनिक की भी जल के अंदर काफी मिलावट के कारण वहां की भी समस्यायें खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में सारे देश को, सारे राष्ट्र को, सारी जनता को विश्वास में लेकर सरकार को यह निर्णय करना पड़ेगा कि अगली शताब्दी में पीने के पानी की समस्या इस देश के अंदर नहीं रहेगी। हम लोग इसको सर्वाधिक प्राथमिकता दें और सर्वाधिक प्राथमिकता दे करके पूरी तरह से कोशिश करें। यह ठीक है कि कई जगह इस पर रिसर्च और अनुसंधान आदि हो रहा है और किस प्रकार से इसमें तेजी लायी जा सकती है इसके बारे में विचार हो रहा है। लेकिन जो राज्यों के अंदर समस्यायें हैं विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की सप्लायी के लिए वहां पर ओवरहेड टैंक्स बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्टर सामने नहीं आते। कई राज्यों में यह देखा गया है कि लक्ष्य 10 हजार का रखा जाता है लेकिन 2 हजार कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उस पर काम लेने के लिए कोई कन्ट्रेक्टर सामने नहीं आता। ऐसी स्थिति में ओवरहेड टैंक जो बिल्कुल कंवेंशनल तरीके के न हो इसके लिए और नया तरीका क्या हो सकता है ताकि तुरन्त लगाया जा सके, यह इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

उसभाध्यक्ष जी, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। इस पर सरकार को, जैसा मैंने निवेदन किया एक निर्णय करना पड़ेगा, इसकी घोषणा करनी पड़ेगी कि हम फलाने साफ तक पीने के पानी की समस्या को सुलझा देंगे और सब को पीने का पानी मुहैया करा देंगे। इस निश्चय के साथ हम लोग अगली शताब्दी में कदम रख सकते हैं। फिर यह जो आजादी की स्वर्ण जयन्ती हम लोग मना रहे हैं इनका कोई मतलब होता है। इसमें जितना भी सहयोग बाकी वालंटरी आर्गेनाइजेशंस का हो सकता है, प्राइवेट कंसर्न्स का हो सकता है वह लिया जाना चाहिए। हर प्रकार के लोगों को इसमें इन्वाल्व कर सकते हैं। यह बात ध्यान में रख करके सरकार इसे प्राथमिकता दें और प्रायरिटी दे तथा एक निश्चित अवधि के अंदर वह पानी मुहैया कराएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अंसारी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

केवल समर्थन करते हैं इतना ही नहीं, उस में सरकार से यह भी मांग की जाए। कि फलों सा में इस पूरा किया जाए। महोदय, बहुत जल्दी की बात पहली पंचवर्षीय यजोना से चल रही है और पिछले 50 साल से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है, लेकिन अगर हर पंचवर्षीय योजना का हिसाब लगाएं तो पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू में तिनेन प्रोब्लेमेटिक विलेजेज थे, उन की संख्या कांस्टेंट रही है। इसलिए सरकार को यह निश्चय करना पड़ेगा कि हम फलों समय के अंदर-अंदर इस कार्य को पूरा कर लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जलालुदीन अंसारी जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, हमारे देश के महान विद्वान रहीम दास जी ने कहा था कि:

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानस, चून।"

महोदया, पूरी धरतदी का 75 प्रतिशत हिस्सा पानी है। जो अन्न हम खाते हैं, उस में पानी का अंश है। सब्जी खाते हैं, उस में भी पानी का अंश है। इसलिए पानी के बिना कोई भी काम अपने ही देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं चल सकता है। इसलिए पानी जैसे इस महत्वपूर्ण सवाल पर जो संकल्प जलालुदीन भाई लाये है, उस का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं क्योंकि आज जो देश की हालत है और पानी का हम जिस तरह से दोहन कर रहे हैं और जैसाकि अंसारी जी ने भी अपने वक्तव्य में कह है, पुराने तौरतरीकों को छोड़कर नए-नए आधुनिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं इस कारण पानी की सतह जाहं है, उस से जीचे जा रही है। पानी को जमा करने का जो हमारा नेचुरल प्रोसेस था और उस पानी को

हम पीने के लिए और अन्य व्यवहार में लाते थे उन सब को छोड़कर हम आज जिस तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस सब से पानी की एक कठिन समस्या देश में निर्मित हो गयी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम आज पानी के माध्यम से इंसेक्टीसाइड्स का उपयोग कर रहे है, जहरीली दवाइयों का उपयोग कीड़े-मकोड़ों को मारने के लिए कर रहे हैं, उस से हमारी भूमि का क्षरण हो रहा है और उस से हम अपनी मातृभूमि को प्रदूषित भी कर रहे हैं। फिर उन रसायनों के प्रयोग से जो अनाज पैदा हो रहा है, उस का भी हम सेवन कर रहे है तो इस कारण से फूड एडल्टरेशन की शिकायत भी हम को मिल रही है। इसलिए मैं संक्षिप्त में इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि आज निश्चित तौर से हमे उन्हीं पुराने तौर-तरीकों पर आना पड़ेगा। महोदय, गांवों में तालाब निर्मित किए जाते थे, लेकिन अब आबादी बढ़ रही है, उस से तालाब भरे जा रहे हैं जबकि पहले सभी गांवों में तालाब रहते थे और उन में पशु-पक्षी, चिड़िया और जीव-जन्तु आकर पानी पिया करते थे। यहां तक कि मनुष भी उस पानी का सेवन किया करता था, लेकिन विकास के बढ़ते दौर में मनुष्य ने उस पानी का पीना छोड़ दिया और चांपाकल और कुएं से पानी पीना शुरू कर दिया।

लेकिन उससे जो जमीन की नमी बनी रहती थी, जो जल का स्तर कायम रहता था, वह जल का स्तर और नमी आज कायम नहीं रह पा रही हैं, जल का स्तर नीचे जा रहा है। यह आज देश के लिए, दुनिया के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, में आग्रह करना चाहूंगा कि पानी की समस्या आज देश के सभी गांवों में बनी हुई है। आज भी हमारे गांव की महिलाएं कोसों-कोस दूर जाकर पानी लाती हैं, ढो-ढो कर पानी लाती हैं। यह जो इस वक्त माह चल रहे हैं, बैशाख और जेठ के, अप्रैल, मई ओर जून, इन तीन माहों में इस देश के लिए पानी की समस्या एक विकराल समस्या हो जाती है, खासकर राजस्थान के लिए, बिहार के कुछ हिस्सों के लिए, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के लिए, जहां लोगों को सही रूप से पानी पीने को भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हम सरकार से यह आग्रह करेंगे कि कम से कम इतना तो जरुर करना चाहिए कि लोगों को पानी की तकलीफ न हो। हमारा पूरा देश अनाज पैदा कर रहा है, अपने खाने भर अनाज पैदा कर रहा है और अगर कमी हो रही है तो विदेशों से मंगवा कर उसकी पूर्ति की जाती है, लेकिन पानी कैसे मंगाएंगे? पानी तो अपने देश में ही काफी है। कभी कभी तो तीन माह देश में पानी ही पानी हो जाता है। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में, हरियाणा में भी और कभी बाढ़ न आने वाले राज्य राजस्थान में भी पानी हो जाता है कुछ खास समय में। तो पानी तो यहां पर पड़ा हुआ है, उस पानी का सही इस्तेमाल करने की जरुरत है, जिससे कि पानी के बिना देश में लोग न मरें।

महोदय, दिल्ली जैसे शहर में पानी के लिए कतार लगानी पड़ती है, क्यू लगानी पड़ती है और कभी कभी दिल्ली के अलावा कई जगह पानी के लिए विवाद हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, आपस में मुकदमा हो जाता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर यह जो पानी की समस्या है, इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। आप जानते हैं, 85 परसेंट भारत गांव में बसता है, इन गांवों के लिए निश्चित तौर पर पीने के पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। महोदय, जलालुदीन भाई जो यह संकल्प लाए हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे आप पानी की व्यवस्था करेंगे। आपको इतनी गारंटी तो करनी होगी कि देश में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। पानी के साथ एक और भी समस्या है और वह यह कि पानी में आयरन, लौह अयस्क काफी मात्रा में मिलता है, जो बीमारी का कारण हो जाता है। लोग कुएं का पानी पीते है और उससे घेंघा जैसा रोग हो जाता है। आज लोग गंदा पानी पीने को विवश हैं, जो कई रोगों का कारण होते है। इसलिए अगर लोगों को शुद्ध जल मिल जाए तो उससे लोगों के बहुत सारे रोगों का निदान स्वतः ही हो जाएगा और इस देश में लोग स्वस्थ होंगे।

अंत में मैं जलालुदीन भाई के इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

(THE VICE-CHAIRMAN [SHRI NARESH YADAV] IN THE CHAIR)

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Sir, this is a fundamental issue for the development of any society and we have got an opportunity to discuss this through a Private Member Resolution moved by Jalaludin Saheb. In recent period, we must positively acknowledge a development in our society. When a person goes to any remote village, the remotest corners of our country, he will find various brands of soft drinks, Coca

Cola, Campa Cola, etc. One can find them in almost all areas of our country. At the same time, there has been a spurt in the growth of mineral water bottles and the companies producing them all over country. Their accessibility has increased. While positively acknowleging the availability of various soft drinks and mineral water, etc., we must express one very unfortunate development which has continued to grip our society. It is that even after completion of eight Five-Year Plans and many more missions that have been mentioned in this House, not more than 20% of our rural population can assert to have sanitary drinking water facility. Although drinking water facility is available to about 50 per cent of our rural population, only 20 per cent of them have access to safe drinking water facility. This is a pathetic state of our country which has completed Eight Five Year Plans and some Annual Plans. It reflects the failure of our entire planning process. I must thank Shri John F. Fernandes who referred to the failure of the planning process and the planners of our country for the last fifty years in this regard. Sir, there are many countries in the world which do not have any rivers, rivulets, sweet-water lakes and other drinking water sources. Yet, if you go through the international records, the publications of UNESCO, UNDP, the World Bank and IMF, you will find that many of these countries had long ago resolved and perpetually solved their drinking water problems. They really have a scarcity of sweet-water lakes. They really have a scarcity of water resources. But ours is a country which has not only tropical climate, regular rainfed land, but also one of the longest stretches of rivers, rivulets, sweet-water lakes and other sources of water. I am leaving apart the coastal areas where we need tremendous amount of modern technology and resources for purification and treatment of water. I am excluding that. That apart, in spite of the drinking water sources that we have in the form of rivers, rivulets, etc. and a large part of our land mass which remains flooded during a significant part of the year, it is very unfortunate that even after 50 years of our independence, we have not been able to fulfil the basic and fundamental item of our agenda of providing safe drinking water facility to our fellow citizens. This is very, very unfortunate, Sir.

Sir, this is a long colonial legacy. The problem of drinking water is centuries old. If at the turn of this millennium, when the 3rd millennium is going to come, the Upper House of Parliament has to discuss this issue, we should be very clear about the real efficacy and effectiveness of the whole planning process and the implementation of the Plans that has been done in the last fifty years. We must thank the new planners, those who have drafted the Approach Paper of the 9th Plan and the Ministry that has been involved in this, that they have assured, not in terms of formation of any Mission or in terms of taking up works, etc. because that has not fulfilled our requirements, but for making a categorical commitment in the Approach Paper to the 9th Plan that in the next five years provision of safe drinking water to hundred per cent of our population will be a priority. There was a duscussion in the National Development Council on the 16th of Jaunary on the Draft Approach Paper of the Ninth Five Year Plan. Prior to that discussion, the Government had called a Conference of the Chief Ministers on basic minimum services. The first item that was selected in that conference was providing safe drinking water to 100 per cent population of our country. We are grateful to them. We hope that our Government will be able to overcome the weaknesses and lapses of the previous eight Plans and Annual Plans in the Ninth Five Year Plan. In our *Shastras*, ancient literatures, works and deeds, water has been made synonymous with the earth. We are living on this earth. But, it was water which came first on this earth. It was not the earth, not the land mass which came first. So far as my knowledge goes, this is how our planet earth was

born. So, a comprehensive drinking management policy should be there. People in other parts of the world, even in far-flung areas and in remote continents, have been making tremendous modern technological achievements for making various uses of water resources, including water, including many other forms of co-generation and regeneration. In certain countries of the world, there has been advanced technology of power generation even from oceans. When this basic fundamental issue has been resolved in many countries of the world, it is still unresolved in our country. I am constrained to point out the failure of the last eight Plans. This is quite unfortunate. This is a national shame that we have to discuss this issue even today. Only now the Chief Ministers Conference was convened by the new Government, prior to the National Development Council meeting, on 16th of January, wherein this issue was discussed on a priority basis. Why did it not come on the agenda all these years? How did it not come on the agenda all these years? If we cannot resolve the problem of safe drinking water management, will other forms of correct utilisation of water resources be available to us? Can we afford to do that? Many other countries have already done a lot in this regard. Therefore, this is a basic issue which needs a lot of attention of the Government. In this regard, a lot has been discussed, many missions have been prepared and a lot of commitments have also been made, but now some correct and concrete steps should be taken in this direction. This requires community involvement, youth participation, participation of rural people. This has been suggested by many hon. Members who have spoken prior to me. There should be participation of school students, teachers and the communities. This can simultaneously be a rural employment generation programme. This can be a patriotic inspiring programme for the youths of our country who can get involved themselves in this process and can feel a kind of involvement in the nation-building for making our country ready not only for the 21st century but for the next millennium.

Sir, the problem of safe drinking water is not confined to the plains. One can very well understand that even in the Gengetic plains of our country, not more than 20 per cent of the rural population can have access to safe drinking water. It is very clear as to what will happen to the people who are living in the Thar desert of Rajasthan.

What will happen to the people who are living in the hill-tops, mountains of the North-Eastern States and certain parts of western India like Garhwal and Kumaon ranges? Waht will happen to the people who are living in Shimla, Manali and in many other remote hill areas where the hilly streams have not been properly utilised and managed for supplying drinking water to the people living over there? One can very well understand as to what will happen to the remotest areas where there is not an adequate level of surface water or that surface water will not continue to remain for more than a decade or even less than that. We all know about it. Unfortunately, it is also a national shame—and I feel ashamed to repeat, but it is our duty—that we still live in a country in many parts of which certain sections of people, certain castes of people do not have any water sources in their own villages. Even today they are not allowed to go to another village dominated by other high castes to fetch water from there. It is a very unfortunate thing. It is very shameful if water is not provided to each and every section of our community, our rural population. Certain castes of our country are still deprived of fetching water from other village dominated by other castes. I am ashamed to repeat, I am ashamed to say this in this House. But, this is a reality. It is quite natural that if people in the Gangetic plains are deprived of safe drinking water, then what will happen to the people living in other areas? So, drinking water is all the more important. It is not only a question of mission. A mission is always welcome.

Many more missions, hundreds of missions are welcome. The missions should be combined. Why should there be a separate water mission or a separate technology mission? If there is a mission in anybody's name, it should also provide sustenance from that mission to update and modernise its techniques so that this mission is effectively implemented. But, I would like to know whether there would be a comprehensive drinking water management policy in the country and whether the mission can fulful the long-left need by a comprehensive drinking water management of country. I am constained to say an opportunity of 50 long years has been wasted by us collectively, and particularly by those who are at the helm of power to reverse the colonial legacy and aberrations so far as taking the message of the mission to the concerned people and so far as taking the safe drinking water to the fellow citizens of country are concerned. Sir, we have wasted an opportunity of long fifty years. Should we waste more? We must thank Mr. Ansari and all the other hon. Memebrs who have spoken on this issue cutting across party affiliations. They have criticised the last eight Five Year Plans in this regard. Sir, some reawakending should be done. Not a single moment should be wasted. We have committed a mistake by wasting 50 years because we have not been able to solve this century-old problem of safe drinking water. It is a not a difficult job. It has been solved in many parts of the world. Even in many developing countries, this problem has been solved. We should give top priority to this problem on our agenda. Sir, in this connection I would like to know that not only in the 9th Plan but also in every future course of action whether there will be a comprehensive mission and a comprehensive plan prepared in this regard. It may be in anybody's name because name does not matter. I would also like to know whether that plan will be confined to the National Development Council or the Ministry concerned. There should be a tremendous, unprecedented community involvement of local government, mass organisations, NGOs, clubs, voluntary organisations so that this project is really implemented. One Chief Minister's Conference has emphasised this. I would like to know from the Government whether the Government will take many more such initiatives, convene conference not only of Chief Ministers but also of the categories and groups which I mentioned just now in order to make effective implementation of this. If there is a comprehensive management, if there is a political will as has been reflected by the NDC meet in the approach to the Ninth Five Year Plan, it is bound to happen and is bound to take place. We are not weak. We are not weak technologically. We are not weak financially and the approach is not unviable that we cannot make it. But what is required is, sustenance and consistency on the part of the Government, a larger community involvement in the entire process. I would just like to mention a few other aspects of the Drinking Water Management System which is afflicting our country. Already there have been mentions about water-brone diseases and many other qualitative aspects of the drinking water. In any country, and quite naturally in our country which is having a tropical weather, where we have a tendency to be more prone to water-brone diseases and many other problems that are associated with this agro-climatic conditions, adequate and specialised care should be taken by drawing lessons from the other countries falling in the agro-climatic zones so that the required medical management of the quality of the water is taken up in right earnest. There is iron deficiency. In West Bengal particularly, in certain districts like Malda and in other places there have been cases of arsenic poison. It is a dangerous thing. If I am correct, arsenic, as reported by a newspaper, is even required for a human body. Arsenic, if mixed beyond a certain quantity with water or if it is in the surface water, can bring lathal diseases and it can become an epidemic in districts where the concentration is beyond a certain quantity.

Unfortunately, certain districts of West Bengal and even certain other districts in India are suffering from arsenic-borne diseases. How is the Government planning to tackle this? The Government of West Bengal, I have first-hand information, had prepared comprehensive projects in order to remove this arsenic contamination with scientific treatment of the contaminated water in those particular districts, blocks, deeper tube-wells, tube-wells, etc. The World Bank's assistance was sought. The World Bank was ready to provide assistance. The Public Health Engineering Minister of West Bengal repeatedly approached the Government at the Centre on many occasions starting from 1991-92 onwards. There were many other initiatives; slides were organised, a public awakening programme was undertaken by the Government of West Bengal, slides were shown in villages, science forums were undertaken, slides were shown at different villages, the Government of West Bengal held people's science forums in the State. There were many other initiatives. But I am constrained to say that it is very unfortunate that the Government of India did not respond in the manner in which it should. Arsenic contamination beyond the alarming level, beyond a minimum level can bring ep-idemic to a block, to an area. Despite the Central Government despite kmowing this did not give adequate assistance. I hope that with re-emphasing of the drinking water problem, and quality drinking water facilities in the approach Paper to the Ninth Five Year Plan and in the concerned agencies, the new Government will look at the matter and will give a renewed thrust and stress to extend the necessary assistance, which is required for tackling this basic problem, this alarming problem in the State of Bengal. It is not only a question of West Bengal, there are many other States where it might not have been explored yet. Because of the Peoples science forum and certain initiatives from the Government in West Bengal in certain blocks, it had been discovered quite early. We cannot be sure that the problem of arsenic contamination is not there in other parts of the country. Unfortunately, there are no people's science movement throughout the length and breadth of the country, which should have been there. There is a lack of community awareness, scientific awareness in our people, and there is a lack of scientific awareness initiative by the State Governments and local bodies in different States. People's science movement is not strong enough everywhere. That is why this problem may remain suppressed, for example, in Rajasthan, in the tribal areas of Madhya Pradesh in the tribal belt, remote belt of Bihar. We have to explore that. That is why a comprehensive modern drinking water management policy is required, which will look into each and every aspect of it, so that the quality of drinking water will be ensured. I am not talking about any particular State, but from the hill-top of Simla, Darjeeling, Assam, Manipur, Nagaland to the salty areas of the Kutch of Gujarat. We have a large sea coast, a large coastal area, and contrary to the popular perception, all of us know that it is very difficult to have quality drinking water in coastal areas because of the salty nature of the water there. So, how to make a perfect and even use of the available drinking water facilities of our country for the entire country, how an evenness can be brought into it, how these remote areas, hilly areas, desert areas, coastal areas can also enjoy the same basic minimum service of quality drinking water as our Gangetic plain people are enjoying—this should form one of the important items of the Comprehensive Drinking Water Management Policy, which we expect will be initiated by this Government during the tenure of this Plan. I further appeal to the Government to take all this into consideration and involve the community. Use it also as a rural employment generation programme for our country. With these words, I thank Shri Jalaludin Ansari Sahib for bringing again a 50 year old agenda on the floor of the House, for the attention of each and everybody. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): बहुत-बहुत धन्यवाद श्री सोलीपेटा रामचन्द्र रेड्डी।

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Vice-Chairman, Sir. I have taken permission to speak in Telugu. Therefore, I am speaking in Telugu.

*Hon'ble Vice Chairman Sir, I have taken permission to speak in Telugu.

Sir, we have completed 50 years of Independence and are proudly celebrating it. While we are enjoying the fresh air of freedom it is unfortunate to realise that there are still lakhs of people struggling to get drinking water and it is high time to solve this problem. It was decided right at the time of Independence that it is the responsibility of the Center and State Governments to supply drinking water to every citizen of the country. We are allocating funds for the same cause in every five year plan. In 1986 we have also introduced National Drinking Water Mission which was called Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission in 1991, the purpose of which was to supply sustainable drinking water throughout the country and also bring in awareness among people regarding the dangers of water borne diseases. Both the Centre and State Governments were to take up this responsibility. But Sir, I support and agree with the concern of Shri Jalaluddin Ansari regarding the supply of drinking water which he expressed through this resolution. I want to bring to the notice of this August House that even today there are lakhs of people struggling due to scarcity of water. Especially in towns where very few taps are provided and people living in slum areas hardly get a pot of drinking water and the acute need for it causes rivalry and enemity among them. They try to quench their thirst with any water available around and so become victims of diseases and die. This drinking water has become a perpetual problem. Inspite of Government spending crores of rupees allocating through Five Year plans we still have 'uncovered villages' and problem villages'. The statistics says that 94,000 villages were covered in five Five-Year plans. The Survey report said that there were still 2.31 lakh villages to be covered under this scheme of providing drinking water. The next survey report of 1985 said that there are 1.62 lakh problem villages. The total problem villages are around two lakhs and the Government both centre and the State promised that they will be covered during the 7th five year plan. They have also promised that every citizen will be provided with 40 litres of pure drinking water and one hand pump for a populaiton of 250 people would be installed. They have also said that care will be taken in those areas where water has impurities like chloride, brackishness aresenic, excess iron etc. But the 'uncovered' and 'problem villages' are increasing day by day instead of decreasing. That is how I say that it is a perpetual problem.

Sir, our records show that there are several covered villages but in reality they are not 'covered' because they install a hand pump and treat it as covered village where as the hand pump does not work. So it cannot be considered as a covered village untill unless people get safe drinking water. If we ask questions we are given a reply that it comes under partially covered village. As far as 40 litres per individual scheme is concerned, it is not implemented even in those villages which are 'covered' according to our records.

Sir, the Centre and State Governments have started schemes like Accelerated Rural water supply programme, Minimum Needs programme through which they intended to cover all the problem villages by the end of 97-98. They said that by the completion of 8th five year plan there will not be a single village suffering from scarcity of water. We have completed our 8th five year plan and entered the ninth five year plan. In the ninth five year plan they intend to see that all the schools are supplied with drinking water considering that the

'problem villages' are no more. But unfortunately there are still a number of villages to be covered under the said schemes.

Sir, every Government, whichever party was in power have been promising that they will solve this problem within two years or three years. But Survey always showed that the promises have not been kept and we all know about it. All the hon. members must have visited villages and found so many hand pumps around. But more than half of the hand pumps would not be in working condition. No body bothers to repair them too.

Sir, there was another scheme called safe drinking water supplying scheme through taps. But even this supply is not regular and for weeks there is no supply of water. Even if it is brought to the notice of the authorities the situation does not improve. What is our responsibility? Is it just fixing a hand pump or a tap? No, it is not. We should see that the water is supplied to every individual. The Government should get a feed back regarding the working of the hand pumps and how many people are really able to benefit by the schemes. The supply is some times there, some times not there. The fact is that the villages still remain without regular supply of drinking water and we are in the same situaton inspite of all our schemes. We say that the Panchayat is responsible as far as hand pumps are concerned and the Panchayat Samiti has to look after the water supply. This has to be mandatory and priority should be given to this problem and required funds are to be allocated and also ensured if the funds are properly utilised. This is the responsibility of both Centre and the State Governments. Otherwise all these schemes will remain on paper and the problem will not be solved. I am grateful to Shri Jalaluddin Ansari for raising this issue through this resolution.

Sir, supporting Shri Ansari's resolution I would also like to draw the attention of the Government to the problems faced by our State also. There are 2587 villages in our State that is Andhra Pradesh, where water is not only impure but also poisonous. There has been a proposal from Prakashan, Krishna, Mehboobnagar, Khammam Cuddapah and Nallagonda districts of 17 projects worth Rs. 599.79 crores requesting the Central Government to allocate funds. So through you Sir, I request the Minister concerned to accept the proposals immediately and help our State Government if we really intend to supply pure drinking water to the people of our country. Accepting the proposals will help us to be successful in our schemes. In Jemmala Madugu area of Cuddapah district there are 113 villages having flourisis affected water. One crore fifty one lakh people are affected by this and so in 1995 a scheme was proposed which costs Rs. 25 crores. Another proposal was sent to the Government in July, 1996 regarding the western part of Chittoor district where 342 villages were involved and the scheme estimated an expenditure of Rs. 14 crores. In Sullurpet of Nellore district 178 villages are affected due to brackish water. To save these villagers the drinking water has to be pumped in from Swarnamukhi or Kalinga rivers. Since this scheme would cost more our Government sent a proposal that 25 percent contribution would be from the State Government whild the total cost was estimated to be Rs. 22 crores. There were some more schemes sent by Udayagiri and Kovvuru.

Sir, you must be aware of our costal districts where fish and prawn culture is very famous but due to this water becomes impure. Supreme Court has also announced lately that pollution is spreading to underground water too. So, taking this into consideration steps should be taken to purify surface water and supply to the people living in costal areas. I support the resolution moved by Shri Jalaluddin Ansari and request the Government to concentrate more on the implementation of the schemes giving not

only priority to this problem but also having a time bound programme, Time bound should be taken seriously and necessary funds should also be allocated within the required time so that the scheme will be successfully implemented. Sir, with these humble requests and suggestions I thank you for giving me this opportunity. Thank you.

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): रेड्डी साहब, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भारतीय भाषा में बोले इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवादालू। अब मैं आग्रह करता हूं श्री जे० चितरंजन साहब से कि अपनी बात रखें।

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice.Chairman, the issue which we are discussing is a very important issue. Priority should have been given to this by the planners as well as the Government. But, unfortunately, even after 50 years of the Independence, we have to think of, or discuss about how to provide pure drinking water to a majority of the people in this country.

Though really we are talking about the requirement of drinking water of the people in the villages, in cities and towns also the situation is not better. There is shortage of drinking water even in the capital city of Delhi. It is almost the same case with most of the State capitals and other major towns and cities. Anyhow, in the case of villages, the situation is now getting much more worse.

As all of us know, a large number of districts in Orissa are reeling under a very heavy drought. There are reports that 35 districts in Madhya Pradesh will be facing a very severe drought. I do not want to narrate all the cases. Therefore, this drought situation is developing in many parts of the country, and this also confounds the problem.

Of course, drinking water is the basic necessity of human life. Water for sanitary purposes is also absolutely necessary. Some 20 years ago, I had been to the Idukki District, one of the mountainous areas in Kerala. I talked to the doctors of the Public Health Centres. They told me that in those areas water-borne diseases were very widespread and that most of the people who went to the Primary Health Centres, were affected by water-borne diseases. Then, I enquired about this. Of course, there are so many rivulets, fountains, streams and small rivers in that area, and water is available, but that water is contaminated, and there are bacteria also in it. This is the reason why the people were affected by water-borne diseases.

In order to afford a healthy life to the people, it is also very necessary to provide pure drinking water to them.

Sir, I would like to emphasise on one more thing. It is about the Common Minimum Programme in which the Seven Basic Minimum-Needs Programme is also included. Last time when I spoke on the working of the Ministry of Planning and Programme Implementation, there also I had referred to it. In the Seven basic Minimum-Needs Programme of the Common Minimum Programme provision of pure drinking water to all the villages is included as one of the items. In the month of July last year, the Prime Minister convened the Chief Ministers' Conference. There all the Chief Ministers had agreed to earnestly implement the Seven Basic Minimum Needs Programme during these three-and-half years so that all these programmes are completed all over the country by the year 2000 A.D. But, after that Conference was over, I do not have any information as to what is going on down below. Of course, decentralisation is very much needed, especially in the case of such a programme, but unless we prepare a very detailed and realistic programme and also elicit the participation of the people, our local bodies like Panchayat institutions basic Panchayats, Municipalities and other connected organisations, we cannot implement this programme on a town by-town and village-by-village basis. I doubt whether such an effort is being made. Of course, the Planning Minister while replying to the debate on the working of

his Ministry had asserted that the Plan is being implemented with political will. I do not dispute that, but, at the same time I am not convinced whether sufficient steps are being taken to implement the programme by the year 2000 A.D. Therefore, I would appeal to the hon. Minister to give more attention to this problem and to work out a detailed programme at every level, eliciting the participation of the people, getting the involvement of the Panchayat institutions and even NGO organisations. We should make an attempt with a political will and determination to see that this programme is completed by the year 2000 A.D. That is the request that I have to make. With these words I conclude.

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष जी। हमारे देश में राज करने वाले लोगों की एक आदत हो गयी है कि वे पहले समस्या पैदा करते हैं और फिर उस का समाधान ढूंढने की चेष्टा करते हैं। महोदय, आज भी आजादी के 50 साल के बाद भी प्रत्येक देशवासी को हवा और पानी पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है जिस के लिए मेरे ख्याल में थोड़े दिनों में पानी के मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल स्फेयर के टेंडर हमें बुलाने पड़ेंगे। महोदय, मुझे याद है, आज से 50 साल पहले जब कि मैंने जीवन प्रारंभ किया था, उस समय मैं फौज में था और सब से पहले मेरी पोस्टिंग जैसलमेर में हुई थी। यह जैसलमेर राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। यहां तीन साल में आधा इंच बरसात होती है। वहां एक आबादी है जिसे पल्ली वालों की आबादी कहा जाता है। वहां आठ सौ वर्ष पुराने रूइंस हैं। उन रूइंस में हम ने वाटर मैनेजमेंट का एक सिस्टम देखा है। महोदय, जैसलमेर के उस इलाके में आधा इंच बरसात होती है और कभी हो गयी तो हो गयी नहीं तो तीन साल कभी नहीं हुई। ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जोकि पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है कभी बहुत सभ्य हुआ करता था वहां पल्ली वालों के चार सौ गांव हैं उजड़े हैं। उन उजड़े हुए गांवों के रूइंस को आप देखिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे उन रूइंस को देखें और उस से वे आठ सौ वर्ष पहले इस देश में पानी मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उसे समझने की कोशिश करें।

महोदय, आज नौवीं योजना के अंदर पांच साल में हिंदुस्तान के सारे गांवों को पीने का पानी देने की बात कही जाती है, लेकिन हमारे देश में इस की प्लानिंग कौन बनाता है? हमारे देश के जो प्लानर हैं, उन को तो यह पता ही नहीं है कि हमारे देश में पानी की कमी कहां है? हमारे देश में चाहे माउंटेन टैरीन लें, चाहे राजस्थान का भू-भाग लें, वहां पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि आज देश की कैपिटल दिल्ली में जहां कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स रहते हैं, वहां भी पानी पूरी तरह नहीं मिल पाता है। वहां टाइम से पानी मिलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलता है। रोज डिकलेयर किया जाता है कि आज दो घंटे इस एरिए में पानी बंद रहेगा, तीन घंटे इस एरिए में बंद रहेगा। अगर देश के वाटर मैनेजमेंट को ठीक नहीं किया गया तो पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाएगा।

मान्यवर, एक तरफ तो पानी की कमी है और दूसरी तरफ उस पानी को पोल्यूट किया जा रहा है। आप स्वयं जिस राज्य के रहने वाले हैं, बिहार, वहां भी और उत्तर प्रदेश के इलाके में, जहां पानी की कमी नहीं थी, पैरालल नदियां थीं, उन तमाम नदियों के पानी को आज दूषित कर दिया गया है एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के नाम पर और कैमिकल फैक्टरीज लगा लगा कर। वह पानी आज पीने लायक नहीं रहा। गांव के अंदर जो ट्रेडीनल पौंड थे, वह समाप्त हो गए। उन पौंडों के जरिए जो पानी रीचार्ज होता था और दिया जाता था, वह सिस्टम आज नहीं रहा। हमारे यहां ग्राउंड वाटर नहीं रहा, सरफेस वाटर हम मैनेज नहीं कर पाए। हमारे देश के सारे हिस्से में साल भर करीब बरसात होती है और उस बरसात के पानी को रोकने में, सरफेस वाटर में हमारी सरकार फेल हो गई। इसमें 60 प्रसेंट पानी समुद्र के अंदर चला जाता है। तो ग्राउंड वाटर नहीं, सरफेस वाटर नहीं, ड्रेन वाटर नहीं, तो आपके पास बचा जरिए हैं? क्या कोई इंटरनेशनल कंपनी अमरीका, इंग्लैंड से आ रही है, वहीं से पानी ला रही रही है? यदि ऐसा है तो बात अलग है। पानी के जो हमारे अपने रिसोर्स हैं, उनके बारे में हमको अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा।

मान्यवर, आठ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम बात करते हैं, जैसा माननीय रेड्डी जी अभी कह रहे थे कि हमारी आठ पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परवाह ही नहीं की गई। रूरल डवलमेंट की शुरूआत भी हुई तो पांच योजनाओं के बाद। पांच पंचवर्षीय योजनाओं तक तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का किसी ने सोचा ही नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): एक मिनट, प्लीज। आप बैठिए। वैसे अभी इस संकल्प पर एक और वक्ता हमारे बोलने वाले हैं, जिनकी पर्ची आयी है। यद्यपि समय हो गया है, अगर इसमें सदन चाहे तो हम

इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे अंसारी साहब को भी बोलना होगा फिर से और माननीय मंत्री जी भी जवाब देंगे। तो जो सदन की राय हो, उस के अनुसार हम काम करेंगे।

श्री शिव चरण सिंह: 6 बजे तक कर लें।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: दूसरे दिन यह हो सकता है तो इसको उस दिन ले लीजिए।

†[شری جلال الدین انصاری: دوسرے دن یہ ہو سکتا ہے تو اسکو اس دن لے لیجئے]

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): संकल्प दूसरे दिन संभव नहीं होता।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: लेकिन यह तो विचार का विषय है कि इतनी चर्चा के बाद आगे विचार ही न हो।

†[شری جلال الدین انصاری: لیکن یہ تو وچار کا وشے ہے کہ اتنی چرچہ کے بعد آگے وچار ہی نہ ہو]

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): तो ऐसा है कि सदन की कार्यवाही सोमवार 11.00 बजे तक के लिए स्थगित कर देते है।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: पहले इसको तय कर लीजिए कि आगे यह होगा या नहीं होगा?

†[شری جلال الدین انصاری: پہلے اسکو طے کر لیجئے کہ آگے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا]

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): नहीं होगा।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: नहीं होगा। तो इसके क्या मायने है?

†[شری جلال الدین انصاری: نہیں ہوگا تو اسکے کیا معنی ہیں]

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव) नहीं, संकल्प में नही होता है।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: मंत्री जी का रिप्लाई होगा?

†[شری جلال الدین انصاری: منتری جی کا ریپلائی ہوگا]

उपसभाध्यक्ष (श्री नरेश यादव): माननीय मंत्री जी का रेप्लाई, आज ही इसको समाप्त किया जाए, तो होता।.........(व्यवधान) मुझको कनक्ल्यूड करने दीजिए।........(व्यवधान).......सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 मई, 1997 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at thirteen minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 12th May, 1997.

---

*[] Transliteration in Arabic script.

140/MP/RSS/ND/98—300 Copies—January 99—MGITBPChdg.